SHAH TIMES
10 September,2019

पीएम ने की देहरादून में उत्कृष्ट केंद्र की घोषणा

भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद के महानिदेशक ने दी जानकारी

शाह टाइम्स ब्यूरो

देहरादून। प्रधानमंत्री द्वारा भूमि निम्नीकरण संबंधित समस्यायों के निदान में दक्षिण-दक्षिण सहयोग बढ़ाने हेतु भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद्, देहरादून में एक उत्कृष्ट केन्द्र की स्थापना की घोषणा की।

दिल्ली में आयोजित मरुस्थलीकरण नियंत्रण हेतु संयुक्त राष्ट्र संधि के पक्षकारों के 14 वे सम्मेलन के हवाले से भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद् के महानिदेशक डा. सुरेश गैरोला ने बताया कि यह उत्कृष्टता केन्द्र

■ **वैज्ञानिक भूमिका को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाने में बढ़ावा मिलेगा**

मरुस्थलीयकरण नियंत्रण हेतु संयुक्त राष्ट्र संधि उत्कृष्टता केन्द्र मरुस्थलीयकरण नियंत्रण हेतु ज्ञान एवं तकनीक का आदान प्रदान करेगा। यह केन्द्र भूमि निम्नीकरण को रोकने के कार्यों की मोनिटेरिंग एवं मूल्यांकन तथा इसका एक डाटा बेस भी तैयार करेगा।

यह वानिकी अनुसंधान एवं भूमि निम्नीकरण की समस्याओं के समाधान एवं भूमि निम्नीकरण की समस्याओं के समाधान हेतु भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद् की वैज्ञानिक भूमिका को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाने में बढ़ावा मिलेगा। देहरादून स्थित भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद्, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार की एक स्वायत्त संस्था हैं, यह संस्था वानिकी अनुसंधान, शिक्षा एवं विस्तार पर भारत वर्ष में विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में स्थित नौ संस्थानों एवं पांच अनुसंधान केन्द्रों के माध्यम से अपने कार्य सम्पादित करती हैं।

JAN BHARAT MAIL
10 September,2019

भारतीय वानिकी अनुसंधान एंव शिक्षा परिषद् देहरादून में एक उत्कृष्ट केन्द्र की स्थापना की घोषणा

देहरादून, संवाददाता। मरूस्थली करण नियंत्रण हेतु संयुक्त राष्ट्र संधि के पक्षकारों के 14वें सम्मेलन के उच्च स्तरीय संभाग के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुये प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सुंयक्त राष्ट्र एंव अंतराष्ट्रीय संस्थानों के प्रमुख, सरकारों के प्रमुख कई देशों के मंत्रियों व विशेषज्ञों की उपस्थिति में कहां कि भूमि निम्नीकरण की समस्याओं के समाधान हेतु वैज्ञानिक दृष्टिकोण और तकनीक के समावेश को बढ़ावा देने हेतु भारत ने भारतीय वानिकी अनुसंधान एंव शिक्षा परिषद् में एक उत्कृष्टता केन्द्र की स्थापना का फैसला लिया है। यह केन्द्र भूमि के निम्नीकरण समस्याओं सम्बन्धित ज्ञान, तकनीक तथा मानव संसाधन के प्रशिक्षण में इच्छुक दक्षिण-दक्षिण सहयोग को बढ़ावा देगा।

वर्तमान में मरूस्थलीयकरण नियंत्रण हेतु संयुक्त राष्ट्र संधि के पक्षकारों का 14वां सम्मेलन भारत में हो रहा हैं। इस घोषणा से वानिकी अनुसंधान एंव भूमि निम्नीकरण की समस्याओं के समाधान एंव भूमि निम्नीकरण की समस्याओं के समाधान हेतु भारतीय वानिकी अनुसंधान एंव शिक्षा परिषद्, की वैज्ञानिक भूमिका को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाने में बढ़ावा मिलेगा। देहरादून स्थित भारतीय वानिकी अनुसंधान एंव शिक्षा परिषद्, पया 'वरण एंव वन मंत्रालय, भारत सरकार की एक स्वरयत संस्था हैं, यह संस्था वानिकी अनुसंधान, शिक्षा एंव विस्तार पर भारत वर्ष में विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में स्थित नौ संस्थानों एंव पाँच अनुसंधान केन्द्रों के माध्यम से अपने कार्य सम्पादित करती हैं।

DAINIK JAGRAN
10 September,2019

सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनेगा आइसीएफआरई

जागरण संवाददाता, देहरादून: भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद (आइसीएफआरई) ने नाम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बड़ी उपलब्धि जुड़ने वाली है। मरुस्थलीकरण नियंत्रण के लिए संयुक्त राष्ट्र संधि के पक्षकार करीब 200 देशों के 14वें सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आइसीएफआरई को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने की घोषणा की। लिहाजा, यह सेंटर विकासशील देशों में लैंड डिग्रेडेशन (भूमि निम्नीकरण) की दिशा में काम कर सकेगा।

आइसीएफआरई के महानिदेशक डॉ. एससी गैरोला ने इस उपलब्धि को साझा करते हुए कहा कि परिषद पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की स्वायत्त संस्था है। इसके अधीन वन अनुसंधान संस्थान (एफआरआइ) जैसे देश में नौ संस्थान व पांच अनुसंधान केंद्र संचालित हो रहे हैं। इनके माध्यम से खदानों के पुनरुत्थान, क्षारीय-ऊसर मृदाओं के सुधार, रेत के टीलों का स्थरीकरण, शीत मरुस्थलों में वनीकरण जैसे तमाम कार्य पहले ही किए जा रहे हैं। राष्ट्रीय रेड्ड प्लास के तहत स्वीकृत परियोजना में भी भूमि के निम्नीकरण रोकने के लिए परिषद बेहतर कार्म कर रही है। अब मरुस्थलीकरण नियंत्रण की दिशा में आइसीएफआरई विकासशील देशों के बीच भूमि के निम्नीकरण रोकने, निम्नीकृत भूमि के सुधार के लिए ज्ञान व तकनीक का आदान प्रदान कर सकेगी। इस दिशा में अंतरराष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों को क्षमता विकास के लिए भी सहयोग किया जाएगा।

उपलब्धि

- लैंड डिग्रेडेशन की दिशा में काम करेगा आइसीएफआइ
- संयुक्त राष्ट्र संधि के पक्षकार देशों के सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने की घोषणा

DAINIK BHASKAR
10 September,2019

2.6 करोड़ हेक्टेयर बंजर भूमि बनाएंगे उपजाऊ

यूएनसीसीडी की 14वीं शिखर बैठक में प्रधानमंत्री ने की घोषणा, जमीनी स्तर पर काम करने से हासिल होंगे लक्ष्य

- **प्लास्टिक को अलविदा कहने की अपील**

ग्रेटर नोएडा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को कहा कि वर्ष 2030 तक देश की 2.6 करोड़ हेक्टेयर बंजर जमीन को ऊपजाऊ बनाया जाएगा।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम सम्मेलन (यूएनसीसीडी) के सदस्य देशों की 2 सितंबर से जारी 14वीं शिखर बैठक के उच्चस्तरीय खंड का उद्घाटन करते हुए कहा कि मैं वैश्विक भूमि एजेंडा के बारे में एक प्रतिबद्धता की घोषणा करना चाहता हूं। पहले वर्ष 2030 तक 2.1 करोड़ हेक्टेयर ऐसी जमीन को ऊपजाऊ बनाने का लक्ष्य रखा था जो बंजर हो चुकी है। आज हम इस लक्ष्य को बढ़ाकर 2.6 करोड़ हेक्टेयर करने की घोषणा करते हैं। इसके अलावा वृक्षादित क्षेत्र बढ़ाकर तीन अरब टन कार्बन का अवशोषण किया जाएगा, जिसका लक्ष्य पहले ढाई अरब टन रखा गया था।

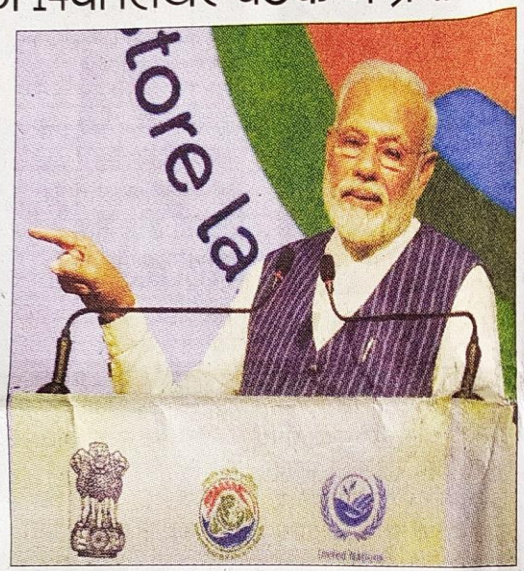

ग्रेटर नोएडा में सम्मेलन को संबोधित करते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। एजेंसी

प्रधानमंत्री ने दुनिया भर के देशों से एक ही बार इस्तेमाल में आने वाले प्लास्टिक को अलविदा कहने और 'वैश्विक जल एजेंडा' तैयार करने का आह्वान करते हुए कह कि जमीन की अनुपजाऊ होने का एक और स्वरूप है, जिस पर हम अभी ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं, लेकिन जिससे निपटना नामुमकिन हो सकता है। प्लास्टिक कूड़ा जमीन को बंजर बना देता है। इसलिए हमने एक ही बार इस्तेमाल हो सकने वाले प्लास्टिक का इस्तेमाल बंद करने का फैसला किया है। हम चाहते कि पूरी दुनिया इस तरह के प्लास्टिक को अलविदा कह दे। तभी हम अपेक्षित परिणाम हासिल कर सकेंगे।

पौधारोपण को छह अरब डॉलर का आवंटन: मोदी ने कहा कि राज्यों को वृक्षारोपण के लिए पिछले सप्ताह ही छह अरब डॉलर के कोष का आवंटन किया गया है। बंजर भूमि को उपजाउ बनाने और मिट्टी की गुणवत्ता सुधारने की दिशा में भारत के प्रयासों का उल्लेख करते हुए कहा कि वर्ष 2015 से 2017 के बीच महज दो साल में देश में वन एवं पेड़-पौधों का क्षेत्र आठ लाख हेक्टेयर बढ़ गया। किसी भी परियोजना के लिए जितने पेड़ काटे जाते ही उतनी ही संख्या में नये पेड़ लगाने की शर्त होती है।

सुधारात्मक कदम उठाने का समय: जे मोहम्मद: संयुक्त राष्ट्र की उपमहासचिव अमीना जे मोहम्मद ने कहा कि बड़े पैमाने पर सुधारात्मक कदम उठाने का समय आ गया है। हमारे पर अब इतना समय नहीं है कि हमने और 10 साल बैठकर इस बात पर बहस करें कि हमें क्या करना चाहिये। एक साथ मिलकर हम पर्यावरण से जुड़े एजेंडा लक्ष्यों को और उंचा भी कर सकते हैं तथा उसे हासिल भी कर सकते हैं। भूमि के बंजर होने के कारण हर वर्ष जीडीपी में 10 प्रतिशत का नुकसान हो रहा है। इससे हर साल 44 अरब अमेरिकी डॉलर का अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है।

भूमि का बंजर होना सबसे बड़ी चुनौती: राल्फ: कैरेबियाई देश सेंट विंसेंट ग्रेनादिन्स के प्रधानमंत्री राल्फ ई गोन्जाल्विस ने कहा कि भूमि का बंजर होना हमारे समय की सबसे बड़ी चुनौती है। हमें यूएनसीसीडी के सदस्य देशों की इस बैठक को नया मार्ग बनाने वाला और ऐतिहासिक बनाने का प्रण लेना चाहिये। उन्होंने भारत और मोदी की तारीफ भी की।

देहरादून में खुलेगा उत्कृष्ट केंद्र, प्रधानमंत्री ने की घोषणा

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भूमि निम्नीकरण की समस्याओं के समाधान के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण और तकनीक के समावेश को बढ़ावा देने के लिए भारत ने भारतीय वानिकी अनुसंधान एंव शिक्षा परिषद् में एक उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना का फैसला लिया हैं। यह केंद्र भूमि के निम्नीकरण समस्याओं संबंधित ज्ञान, तकनीक तथा मानव संसाधन के प्रशिक्षण में इच्छुक दक्षिण-दक्षिण सहयोग को बढ़ावा देगा। इस घोषणा से वानिकी अनुसंधान एंव भूमि निम्नीकरण की समस्याओं के समाधान एंव भूमि निम्नीकरण की समस्याओं के समाधान के लिए भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद की वैज्ञानिक भूमिका को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाने में बढ़ावा मिलेगा।

ट्विटर पर पीएम मोदी के प्रशंसक हुए 5 करोड़

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के माइक्रोब्लागिंग साइट ट्विटर पर लोकप्रियता लगातार बढ़ती जा रही है और उनके प्रशंसकों की संख्या पांच करोड़ पर पहुंच गई है। मोदी जनवरी 2009 में ट्विटर से जुड़े हैं। प्रधानमंत्री के ट्विटर हैंडल के अनुसार उनके प्रशंसकों की संख्या पांच करोड़ पर पहुंच गई है। ट्विटर पर प्रशंसकों के मामले में अमेरिका के राष्टपति डोनाल्ड ट्रंप उनके अभी भी काफी आगे हैं। ट्रंप के ट्विटर पर प्रशंसकों की संख्या छह करोड़ 41 लाख है।

सदी के महानायक अमिताभ बच्चन के ट्विटर पर प्रशंसक तीन करोड़ 84 लाख हैं। अमित शाह के ट्विटर फोलोवर्स एक करोड़ 52 लाख हैं। शाह मई 2013 में ट्विटर से जुड़े हुए हैं।

RASHTRIYA SAHARA
10 September,2019

आईसीएफआरई के नाम उपलब्धि, स्थापित होगा उत्कृष्ट केंद्र

■ सहारा न्यूज ब्यूरो

देहरादून।

भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद (आईसीएफआरई) के नाम एक और बड़ी उपलब्धि जुड़ी है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देहरादून स्थित आईसीएफआरई में भूमि निम्नीकरण से संबंधित समस्याओं के निदान में सहयोग बढ़ाने हेतु एक उत्कृष्ट केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। पीएम ने सोमवार को ग्रेटर नोएडा में आयोजित 12 दिवसीय कॉप-14 सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए इस बात की घोषणा की है। इस सम्मेलन में कई देशों के प्रतिनिधि शिरकत कर रहे हैं।

कहा कि भूमि निम्नीकरण की समस्याओं के समाधान हेतु वैज्ञानिक दृष्टिकोण और तकनीक के समावेश को बढ़ावा देने हेतु भारत ने भारतीय वानिकी अनुसंधान एंव शिक्षा परिषद् में एक उत्कृष्टता केन्द्र की स्थापना का फैसला लिया हैं। आईसीएफआरई केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त संस्थान है। यहां पर नया स्थापित होने वाला केंद्र भूमि के निम्नीकरण समस्याओं से संबंधित ज्ञान, तकनीक व मानव संसाधन के प्रशिक्षण में इच्छुक दक्षिण-दक्षिण सहयोग को बढ़ावा देगा। पीएम द्वारा की गई घोषणा से परिषद के वैज्ञानिक गद्गद हैं। आईसीएफआरई के महानिदेशक डा. सुरेश चंद्र गैरोला ने कहा कि इससे वानिकी अनुसंधान व भूमि निम्नीकरण की समस्याओं के समाधान परिषद की वैज्ञानिक भूमिका को वैश्विक स्तर पर पहचान मिलेगी। परिषद के वैज्ञानिकों ने खदानों के पुनरुत्थान, क्षारीय व उसर मृदाओं के सुधार, रेत के टीलों का स्थिरीकरण, शीत मरूस्थलों में वनीकरण, वायुरोधक कृषि वानिकी तंत्रों का विकास तथा हरित कौशल विकास कार्यक्रम में उत्कृष्ट कार्य किया है।

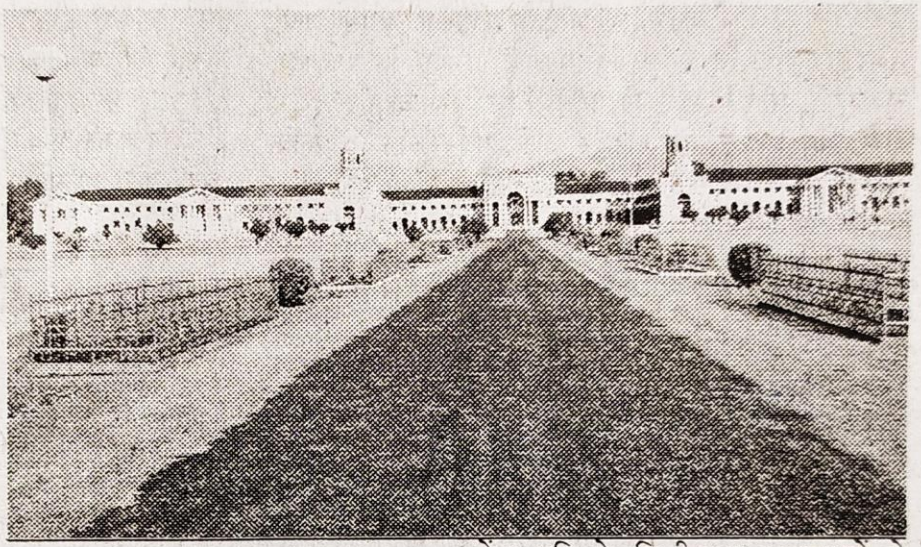

पीएम मोदी ने की भूमि निम्नीकरण से संबंधित समस्याओं के निदान को उत्कृष्ट केंद्र स्थापित करने की घोषणा

परिषद की वैज्ञानिक भूमिका को मिलेगी वैश्विक स्तर पर पहचान, तकनीक का होगा आदान-प्रदान

वनों की उत्पादकता व किसानों की आय बढ़ाने हेतु वृक्षों की उन्नत किस्मों का विकास भी यहां पर किया गया है। परिषद द्वारा तैयार की गई निर्वनीकरण एंव वन निम्नीकरण की समस्याओं के समाधान हेतु रेड्डु प्लस रणनीति को भारत सरकार पूर्व में ही स्वीकृत कर चुकी है। महानिदेशक डा. गैरोला ने बताया कि यह उत्कृष्टता केन्द्र मरूस्थलीयकरण नियंत्रण हेतु संयुक्त राष्ट्र संधि के विकासशील सदस्य देशों के बीच भूमि के निम्नीकरण को रोकने एंव निम्नीकृत्त भूमि के सुधार हेतु ज्ञान व तकनीक का आदान-प्रदान करेगा। जोकि जैवविविधता संरक्षण, खाद्य वजल सुरक्षा, जीविकोपार्जन के साथ ही पर्यावरणीय सेवा के सुधार से उन्नति लाने में सहायक होगा।

AMAR UJALA
10 September,2019

'सिंगल यूज प्लास्टिक' को अलविदा कहे दुनिया : मोदी

ग्रेटर नोएडा में वैश्विक सम्मेलन कॉप-14 : 200 देशों के प्रतिनिधि, 70 पर्यावरण मंत्री और दुनियाभर के 8000 से अधिक प्रतिभागियों को पीएम ने किया संबोधित

अमर उजाला ब्यूरो

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दुनिया से 'सिंगल यूज प्लास्टिक' को अलविदा कहने का समय आ गया है। भारत अगले वर्षों में इसका इस्तेमाल बंद कर देगा।

बढ़ते मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए कॉन्फ्रेंस ऑफ़ पार्टीज (कॉप) के 14वें वैश्विक सम्मेलन में सोमवार को मोदी ने कहा, भारत पर्यावरण, बंजर भूमि व सिंगल यूज प्लास्टिक खत्म करने के लिए संकल्पबद्ध है। सम्मेलन में 200 देशों के प्रतिनिधि, 70 पर्यावरण मंत्री और आठ हजार से अधिक प्रतिभागी आए हैं।

मोदी ने भारत की आदिकाल से पर्यावरण और धरती को अनन्य मानने की परंपरा का उल्लेख किया। कहा, खुशी की बात है कि भारत दुनिया को एक मंच पर लाकर इस पर चिंतन कर रहा है। ऋग्वेद के प्रकृति की आराधना मंत्र का उल्लेख करते हुए मोदी ने कहा, भारत की कामना है कि पूरी धरती, अंतरिक्ष, जल और वायु स्वच्छ और स्वस्थ रहे।

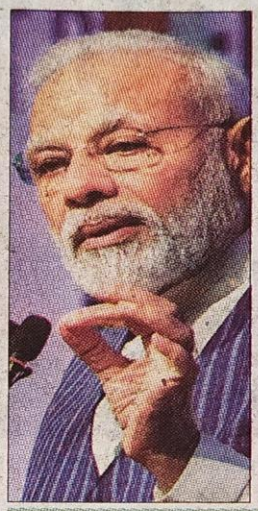

प्लास्टिक कचरा बड़ी समस्या

सम्मेलन में हिस्सा ले रहे देशों का स्वागत करते हुए पीएम ने कहा, प्लास्टिक कचरा मरुस्थलीकरण बढ़ा रहा है। यह स्वास्थ्य और धरती की उर्वरता दोनों के लिए ही बड़ी समस्या है।

दुनिया की मदद करने को तैयार भारत

पीएम ने कहा, भारत भूमि उपजाऊ बनाने के लिए रिमोट सेंसिंग व अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का भी इस्तेमाल कर रहा है। हम अन्य मित्र देशों की मदद करने को भी तैयार हैं।

पेयजल पर बने वैश्विक एजेंडा

मोदी ने पेयजल कमी पर दुनिया से मिलकर चिंतन करने की बात कही। साथ ही संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण प्रतिरोध सभा के नेतृत्व से वैश्विक जल कार्रवाई एजेंडा बनाने का आह्वान भी किया।

2.6 करोड़ हेक्टेयर भूमि बनाएंगे उपजाऊ

मोदी ने 2030 तक देश में बंजर भूमि को उपजाऊ बनाने का लक्ष्य 2.1 करोड़ हेक्टेयर से बढ़ाकर 2.6 करोड़ हेक्टेयर करने की घोषणा की। उन्होंने बताया कि भारत में 2015 और 2017 के बीच पेड़ और जंगल का दायरा आठ लाख हेक्टेयर बढ़ा है। जैविक खेती के साथ-साथ माइक्रो इरिगेशन, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग से उपजाऊ जमीन तैयार करने का काम हो रहा है।

33% हरियाली बढ़ाने का लक्ष्य : जावड़ेकर

कॉप-14 में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि मरुस्थलीकरण रोकने के लिए नई दिल्ली घोषणा पत्र का मसौदा लगभग तैयार हो गया है। इसे मंगलवार को जारी किया जा सकता है। पांच वर्षों में हरियाली बढ़ाने के अनुपात में 24 फीसदी का इजाफा हुआ है, जो कि करीब 15 हजार वर्ग किलोमीटर क्षेत्र है। आने वाले वर्षों में इस लक्ष्य को बढ़ाकर 33 फीसदी तक लाएंगे।

2030 तक देश में 40 फीसदी होगी अक्षय ऊर्जा : जावडेकर

ग्रेटर नोएडा। 2030 तक देश में कुल ऊर्जा का 40 फीसदी हिस्सा अक्षय ऊर्जा होगा। सोमवार को संयुक्त राष्ट्र के मरुस्थलीकरण से सामना मुद्दे पर कॉप-14 अध्यक्ष और भारत के वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन संरक्षण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने यह बात कही। संयुक्त राष्ट्र की उप महासचिव अमीना जे. मोहम्मद और कार्यकारी सचिव यूएनसीसीडी इब्राहिम थियाव ने मरुस्थलीकरण से बचाव के लिए देशों से गंभीर कदम उठाने को कहा। वहीं, प्रकाश जावडेकर ने एक प्रश्न पर सफाई देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने प्लास्टिक से स्वेच्छा से दूरी बनाने की बात कही है न कि प्लास्टिक उत्पादों पर बैन लगाने की। वहीं, 1.3 करोड़ से बढ़ाकर 2.1 करोड़ हेक्टेयर बंजर भूमि को उपजाऊ बनाने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने पीएम मोदी के मरुस्थलीकरण से संघर्ष के लिए सरकार की ओर से चलाई जा रही मुहिम में देहरादून में सेंटर फॉर एक्सीलेंस केंद्र जल्द से जल्द बनाने की बात को आगे बढ़ाया। साथ ही कहा कि इस केंद्र का फायदा अन्य देशों को दिया जाएगा। ब्यूरो

केंद्रीय पर्यावरण मंत्री, देहरादून में बनेगा सेंटर फॉर एक्सीलेंस केंद्र

GARHWAL POST
10 September,2019

PM announces setting up of Centre of Excellence at ICFRE

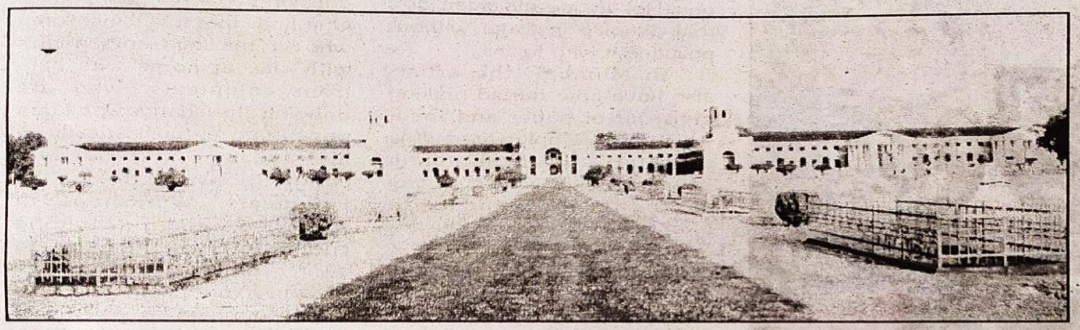

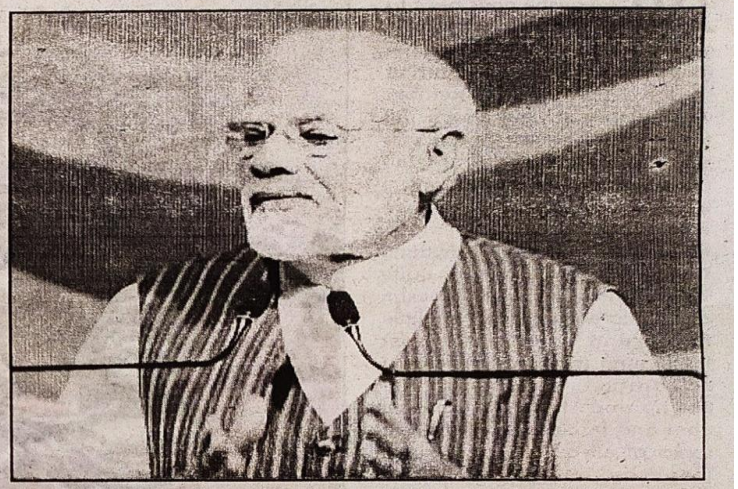

By OUR STAFF REPORTER

DEHRADUN, 9 Sep: Prime Minister Narendra Modi, while inaugurating the High Level Segment of Conference of Parties to United Nations Convention to Combat Desertification (UNCCD) in the presence of heads of the UN and other international organisations, leaders of states and ministers from many countries, announced today that in order to further develop our scientific approach and facilitate induction of technology to land degradation issues, India has decided to set up a Centre of Excellence at Indian Council of Forestry Research and Education. This agency will actively engage to promote South-South cooperation with those who may wish to access knowledge, technology, and training of manpower to address land degradation related issues. Currently, 14th Conference of Parties (COP-14) of UNCCD is being held in India from 2 to 13 September, 2019.

This is a major boost to the recognition of the global scientific role of Indian Council of Forestry Research and Education (ICFRE) in addressing major forestry research and land degradation issues. ICFRE, based in Dehradun, is an autonomous body of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India, which carries out its programmes on forestry research, education and extension through a network of its nine Institutes and five centres spread across various geographic zones in the country. ICFRE has done significant work on development of models for restoration of mined out areas, reclamation of sodic soil and saline lands, sand dune stabilisation, cold desert afforestation, development of windbreak agroforestry system, and green skills development programme.

ICFRE has also developed high yielding varieties of various tree species to improve productivity and augment farmers' income. Government of India has approved National REDD+ Strategy developed by ICFRE in 2018 to address deforestation and land degradation.

The main role of the Centre of Excellence would be to share knowledge and technology amongst developing countries of UNCCD to arrest further land degradation and restoration of degraded lands aiming at conserving biodiversity, food and water security, support livelihoods along with maintaining the flow of ecosystem goods and services for posterity. It will facilitate networking of national and international institutions working on land sustainability and ecosystem management for knowledge sharing, capacity building of the stakeholders in land degradation neutrality (LDN) target setting and provide technical support for land degradation mapping with better resolution for developing countries. It will also be engaged in developing planning, monitoring and evaluation systems for interventions to combat land degradation through creation of a database and knowledge sharing systems.

Although the UNCCD Secretariat is helping the developing country parties build their capacities in achieving LDN targets by 2030 but, still, there are a lot of gaps in capacities of the developing countries for achieving their LDN targets which shall be addressed through establishment of this South-South Centre of Excellence on land degradation.

Target 15.3 of Sustainable Development Goal 15 aims to combat desertification, restore degraded land and soil, including land affected by desertification, drought and floods, and strives to achieve a land degradation-neutral world by 2030. The concept of land degradation neutrality (LDN) is a strong vehicle for driving the implementation of the Convention. Land Degradation Neutrality aims to sustain the productivity of land, maintain the land based natural capital, support sustainable flow of ecosystem goods and services and thus meets the needs of present and future generations. The LDN concept aims to achieve a balance between anticipated new land degradation and future efforts to improve degraded land through land restoration and sustainable land management, etc.

THE HAWK
10 September,2019

PM Announces Setting Up Of Centre Of Excellence In India At The ICFR & Education

Dehradun: Hon'ble Prime Minister Shri Narendra Modi while inaugurating the High Level Segment of Conference of Parties to United Nations Convention to Combat Desertification (UNCCD) in the presence of heads of the UN and other international organizations, leaders of states and ministers from many countries,announced today thatin order to further develop our scientific approach and facilitate induction of technology to land degradation issues, India has decided to set up a Centre of Excellence at Indian Council of Forestry Research and Education. This agency will actively engage to promote South-South cooperation with those who may wish to access knowledge, technology, and training of manpower to address land degradation related issues. Currently, 14th Conference of Parties (COP-14) of UNCCD is being held in India from 2 to 13 September 2019.

This is a major boost to the recognition of the global scientific role of Indian Council of Forestry Research and Education (ICFRE) in addressing major forestry research and land degradation issues. ICFRE based atDehradun is an autonomous body of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India, which carries out its programs on forestry research, education and extension through a network of its nine Institutes and five centres spread across various geographic zones in the country. ICFRE has done significant work on development of models for restoration of mined out areas, reclamation of sodic soil and saline lands, sand dune stabilization, cold desert afforestation, development of windbreak agroforestry system and green skills development program. ICFRE has also developed high yielding varieties of various tree species to improve productivity and augment farmers' income.Government of India has approved National REDD+ Strategy developed by ICFRE in 2018 to address deforestation and land degradation. The main role of the Centre of Excellence would be to share knowledge and technology amongst developing countries of UNCCD to arrest further land degradation and restoration of degraded lands aiming at conserving biodiversity, food and water security, support livelihoods alongwith maintaining the flow of ecosystem goods and services for posterity. It will facilitate networking of national and international institutions working on land sustainability and ecosystem management for knowledge sharing, capacity building of the stakeholders in land degradation neutrality (LDN) target setting andprovide technical support for land degradation mapping with better resolution for developing countries. It will also be engaged in developing planning, monitoring and evaluation systems for interventions to combat land degradation through creation of a database and knowledge sharing systems. Although UNCCD Secretariat is helping the developing country parties to build their capacities in achieving LDN targets by 2030 but still there are a lot of gaps in capacities of the developing countries for achieving their LDN targets which shall be addressed through establishment of this South-South Centre of Excellence on land degradation.

Target 15.3 of Sustainable Development Goal 15 aims to combat desertification, restore degraded land and soil, including land affected by desertification, drought and floods, and strive to achieve a land degradation-neutral world by 2030. The concept of land degradation neutrality (LDN) is a strong vehicle for driving the implementation of the Convention.Land Degradation Neutrality aims to sustain the productivity of land, maintain the land based natural capital, support sustainable flow of ecosystem goods and services and thus meets the needs of present and future generations.LDN concept aims to achieve a balance between anticipated new land degradation and future efforts to improve degraded land through land restoration and sustainable land management etc. Achieving land degradation neutrality - by preventing land degradation and rehabilitating already degraded land, scaling up sustainable land management and accelerating restoration initiatives - is a pathway to greater resilience and security for all. Restoring the soils of degraded ecosystems has the potential to store up to 3 billion tons of carbon annually.

THE HIMACHAL TIMES
10 September,2019

Centre of Excellence to be set up at ICFRE

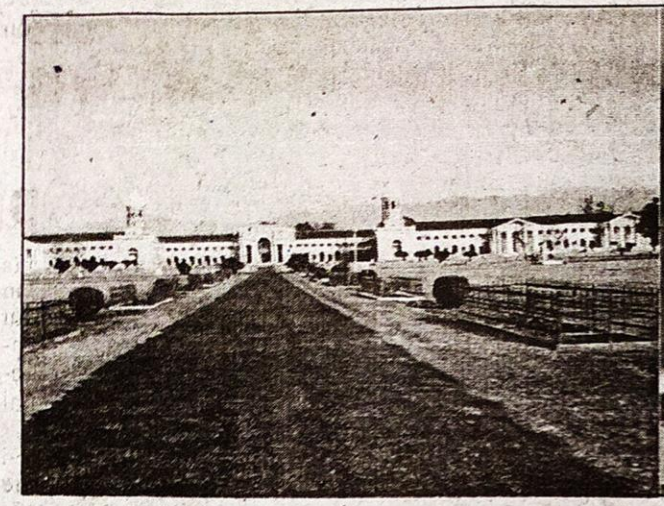

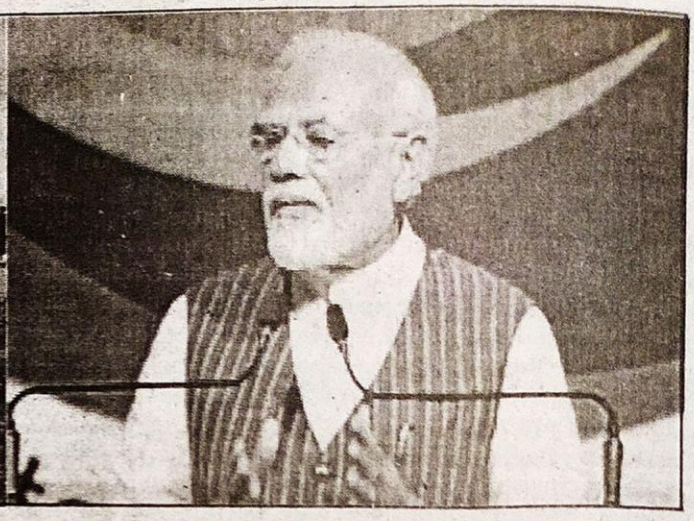

DEHRADUN. SEPT 9 (HTNS) A Centre of Excellence will be set up in India at the Indian Council of Forestry Research and Education to promote South-South co-operation for addressing land degradation issues. This was announced by Prime Minister Narendra Modi on Monday while inaugurating the high level Segment of Conference of Parties to United Nations Convention to Combat Desertification (UNCCD) in the presence of heads of the UN and other international organizations, leaders of states and ministers from many countries.

During his address, the PM said that in order to further develop our scientific approach and facilitate induction of technology to land degradation issues, India has decided to set up a Centre of Excellence at Indian Council of Forestry Research and Education.

This ageney will actively engage to promote South-South cooperation with those who may wish to access knowledge, technology and training of manpower to address land degradation related issues. Currently, 14th Conference of Parties (COP-14) of UNCCD is being held in India from 2 to 13 September .

This is a major boost to the recognition of the global scientific role of Indian Council of Forestry Research and Education (ICFRE) in addressing major forestry research and land degradation issues. ICFRE based at Dehradun is an autonomous body of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India. It carries out programs on forestry research, education and extension through a network of its nine institutes and five centres spread across various geographic zones in the country.

ICFRE has played significant role on development of models for restoration of mined out areas, reclamation of sodic soil and saline lands, sand dune stabilization, cold desert afforestation, development of windbreak agroforestry system and green skills development program.

ICFRE has also developed high yielding varieties of various tree species to improve productivity and augment farmers' income. Government of India has approved National REDD+ Strategy developed by ICFRE in 2018 to address deforestation and land degradation.

The main role of the Centre of Excellence would be to share knowledge and technology amongst developing countries of UNCCD to arrest further land degradation and restoration of degraded lands aiming at conserving biodiversity, food and water security, support livelihoods alongwith maintaining the flow of ecosystem goods and services for posterity. It will facilitate networking of national and international institutions working on land sustainability and ecosystem management for knowledge sharing, capacity building of the stakeholders in land degradation neutrality (LDN) target setting and provide technical support for land degradation mapping with better resolution for developing countries.

It will also be engaged in developing planning, monitoring and evaluation systems for interventions to combat land degradation through creation of a database and knowledge sharing systems.

Although UNCCD Secretariat is helping the developing country parties to build their capacities in achieving LDN targets by 2030 but still there are a lot of gaps in capacities of the developing countries for achieving their LDN targets which shall be addressed through establishment of this South-South Centre of Excellence on land degradation.

The concept of land degradation neutrality (LDN) is a strong vehicle for driving the implementation of the Convention. Land Degradation Neutrality aims to sustain the productivity of land, maintain the land based natural capital, support sustainable flow of ecosystem goods and services and thus meets the needs of present and future generations.

Restoring the soils of degraded ecosystems has the potential to store up to 3 billion tons of carbon annually.

HINDUSTAN TIMES
10 September,2019

ICFRE Campus in Dehradun where the Centre of Excellence announced by PM Modi would be set up. HT PHOTO

Centre of excellence at Doon's ICFRE

HT Correspondent
letters@hindustantimes.com

DEHRADUN: Prime Minister Narendra Modi while speaking at the 14th Conference of Parties (COP-14) of United Nations Convention to Combat Desertification announced the opening of a centre of excellence at Dehradun-based Indian Council of Forestry Research and Education (ICFRE), said a statement by the institute on Monday.

The main role of the centre would be to share knowledge and technology among developing countries of UNCCD to arrest further land degradation and work on restoration of degraded lands aiming at conserving biodiversity, food and water security, support livelihoods along with maintaining the flow of ecosystem goods and services for posterity.

The centre will also engage in developing planning, monitoring and evaluation systems for interventions to combat land degradation through creation of a database and knowledge sharing systems. SC Gairola, director general of ICFRE said, "This is a major boost to the recognition of the global scientific role of the institute in addressing major forestry research and land degradation issues."

ICFRE is an autonomous body under the Union ministry of environment, forest and climate change, which carries out programmes on forestry research. Last year, the central government approved National REDD+ Strategy developed by the institute to address deforestation and land degradation.

THE PIONEER
10 September,2019

PM announces setting up of Centre of Excellence at ICFRE

PNS ■ DEHRADUN

Prime Minister Narendra Modi, while inaugurating the High Level Segment of Conference of Parties to United Nations Convention to Combat Desertification (UNCCD), announced that in order to further develop scientific approach and facilitate induction of technology to land degradation issues, India has decided to set up a centre of excellence at Dehradun-based Indian Council of Forestry Research and Education (ICFRE).

This agency will actively engage to promote South-South cooperation with those who may wish to access knowledge, technology, and training of manpower to address land degradation related issues. Currently, 14th Conference of Parties (COP-14) of UNCCD is being held in India from September 2 to 13.

This is a major boost to the recognition of the global scientific role of ICFRE in addressing major forestry research and land degradation issues. ICFRE has done significant work on development of models for restoration of mined out areas, reclamation of sodic soil and saline lands, sand dune stabilisation, cold desert afforestation, development of windbreak agroforestry system and green skills development program.

It has also developed high yielding varieties of various tree species to improve productivity and augment farmers' income.

The main role of the Centre of Excellence would be to share knowledge and technology among developing countries of UNCCD to arrest further land degradation and restoration of degraded lands aiming at conserving biodiversity, food and water security, support livelihoods along with maintaining the flow of ecosystem goods and services for posterity. It will facilitate networking of national and international institutions working on land sustainability and ecosystem management for knowledge sharing, capacity building of the stakeholders in land degradation neutrality (LDN) target setting and provide technical support for land degradation mapping with better resolution for developing countries.

It will also be engaged in developing planning, monitoring and evaluation systems for interventions to combat land degradation through creation of a database and knowledge sharing systems.

TIMES OF INDIA
10 September, 2019

ICFRE to have first Centre of Excellence in India

Shivani.Azad@timesgroup.com

Dehradun: Indian Council of Forestry Research and Education (ICFRE) Dehradun will have country's first Centre of Excellence to address land degradation issues for enhanced South-South cooperation. ICFRE will lend scientific and technological support to member countries of United Nations Convention to Combat Desertification (UNCCD) by developing planning, monitoring and evaluation systems for interventions to combat land degradation through its rich database.

The prime motive would be to achieve target 15.3 of Sustainable Development Goals (SDG) 15 of United Nations that aims to combat desertification, restore degraded land and soil, including land affected by desertification, drought and floods and strive to achieve a land degradation-neutral world by 2030. The step would also strengthen relations of south nations.

Confirming the development, director-general of ICFRE, S.C. Gairola, told TOI, "India will have a Centre of Excellence for all the nations at ICFRE. This announcement was made today by the prime minister while inaugurating the high level segment of Conference of Parties (COP-14) to the UNCCD at Greater Noida in the presence of heads of the United Nations and other global organisations."

The main role of the Centre of Excellence would be helping the developing countries of UNCCD to arrest further land degradation for conserving biodiversity, food and water security, support livelihoods alongwith maintaining the flow of ecosystem goods and services for posterity.

Gairola said, "Achieving land degradation neutrality - by preventing land degradation and rehabilitating already degraded land, scaling up sustainable land management and accelerating restoration initiatives - is a pathway to greater resilience and security for all. Restoring the soils of degraded ecosystems has the potential to store up to 3 billion tonnes of carbon annually."

PUNJAB KESARI
12 SEPTEMBER,2019

आईसीएफआरई में स्थापित होगा सेंटर फार एक्सीलेंस

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में घोषणा

देहरादून, 11 सितंबर (स.ह.) : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देहरादून स्थित भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद (आईसीएफआरई) में भूमि के निम्नीकरण रोकने (लैंड डीग्रेडेशन रोकने) के लिए उत्कृष्ट केंद्र की स्थापना करने की घोषणा से अधिकारी और वैज्ञानिक उत्साहित हैं। ध्यान योग्य है कि पीएम मोदी ने सोमवार को मरुस्थलीकरण नियंत्रण के लिए संयुक्त राष्ट्र संधि के पक्षकारों के चौदहवें सम्मेलन में यह घोषणा की है। अब आईसीएफआईई में सेंटर फार एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी।

आईसीएफआरई के महानिदेशक डा. एससी गैरोला ने बताया कि प्रधानमंत्री की इस घोषणा से संस्थान को अंतर्राष्ट्रीय महत्व मिलेगा। यहां स्थापित होने वाला केंद्र भूमि के निम्नीकरण समस्याओं से संबंधित ज्ञान, तकनीक तथा मानव संसाधन के प्रशिक्षण में इच्छुक विकसित देशों के वैज्ञानिकों को प्रोत्साहित करेगा। हम अपने ज्ञान व अनुभव को दूसरे देशों में साझा कर सकेंगे। उन्होंने जानकारी दी कि भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद ने खादानों के पुनरुथान, क्षारीय तथा उसर मृदाओं में सुधार, रेत के टीलों के स्थिरीकरण, शीत मरुस्थलों में वनीकरण, वायुरोधक कृषि वानिकी तंत्रों व हरित कौशल क्षेत्र में अभूतपूर्व काम किए हैं।

यह केंद्र भूमि निम्नीकरण को रोकने के लिए कार्य की मानिटरिंग करने के साथ ही मूल्यांकन व इसका एक डाटाबेस भी तैयार करेगा। वैज्ञानिक आरएस रावत ने कहा कि महानिदेशक डा. सुरेश चंद्र गैरोला के नेतृत्व में केंद्र विश्वस्तरीय काम करेगा। इससे हमारे ज्ञान को वैश्विक मान्यता मिली है।

आईसीएफआरई के महानिदेशक बोले-अब हम वैश्विक स्तर पर छाएंगे